



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062022-236720
CG-DL-E-21062022-236720

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 21, 2022/ज्येष्ठ 31, 1944

No. 441]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 21, 2022/JYAISHTHA 31, 1944

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2022

सा.का.नि. 462(अ).—दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए कुछ नियमों का निम्नलिखित मसौदा, जिसे केंद्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 की 49) की धारा 100 की उप-धाराओं (1) और (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त धारा की उप-धारा (1) के अनुसार इस से प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रस्तावित करती है; और एतद्वारा यह सूचना प्रदान की जाती है कि उक्त मसौदा नियमों को उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता के लिए उपलब्ध करवाई जाती है;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो, श्री डी के पांडा, अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, कमरा नंबर 518, 5 वीं मंज़िल, पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003 को, संबोधित किये जा सकते हैं अथवा panda.dk@nic.in पर ई मेल से प्रेषित किये जा सकते हैं;

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

- लघु शीर्ष और सीमा-** (1) यह नियम दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2022 कहे जा सकते हैं।
(2) यह नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में, नियम (15) के उप-नियम (1) में, अनुच्छेद (क) के लिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

“(क) भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, द्वारा पत्र संख्या 28012/09/2019-W3, दिनांक 27 दिसंबर, 2021 के माध्यम से जारी और समय-समय पर संशोधित, हॉर्मोनाइज्ड गाइडलाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया – 2021 में विनिर्दिष्ट है जो

https://drive.google.com/file/d/1d4dedBt2cw-JEvY_qqSodQ9ENfOyNfef/view पर उपलब्ध है ;”।

[फा. सं. 38-05/2022-डीडी-III (भाग -1)]

राजेश यादव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2022

G.S.R. 462(E).—The following draft of certain rules to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri D.K. Panda, Under Secretary to the Government of India, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Room No 518, 5th Floor, Pandit Deen Dayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi, 110003 or by email at panda.dk@nic.in;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and extent.— (1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in rule (15), in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) Standard for public buildings as specified in the Harmonised Guidelines and Standards for Universal Accessibility in India – 2021, issued by the Government of India, Ministry of Housing and Urban Affairs vide letter no. 28012/09/2019-W3, dated the 27th December, 2021, as amended from time to time and made available on https://drive.google.com/file/d/1d4dedBt2cw-JEvY_qqSodQ9ENfOyNfef/view;”.

[F. No. 38-05/2022-DD-III (Part -1)]

RAJESH YADAV, Jt. Secy.